change in the provision relating to "the special responsibility" of the Governor. The proposals have been examined in the Ministry. It does not seem possible to specify any time limit as the proposals also involve Constitutional amendments.

बांगला देश से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए अनुदेश

1528. श्री बलराम सिंह यादव :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बांगला देश से भारत में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए हाल ही में कोई अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सीमा से अवैध प्रवेश रोकने के लिए हाल ही में असम सरकार ने अतिरिक्त प्रबन्ध किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे थे ;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां थीं ; और

(घ) क्या देश की पूर्वोत्तर सीमा पर बाड़ लगाने के काम को पूरा कर लिया गया है; यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) राज्य में अवैध रूप से होने वाले प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए बड़ी संख्या में पदों को सृजित करने से संबंधित प्रस्ताव असम सरकार से प्राप्त हुआ था । इन प्रस्तावों को व्यवहारिक नहीं पाया गया ।

(घ) असम में (158 कि०मी०) और मिजोरम में (231 कि०मी०) के क्षेत्र में बाड़ लगाने का काम चल रहा है। आशा की जाती है कि मार्च, 1996 तक परियोजना के एक बड़े भाग का काम पूरा हो जाएगा ।

देश में कागज का उत्पादन करने वाले रूग्ण एकक

1529. श्री बलराम सिंह यादव :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 270 कागज उत्पादक एककों में से 115 एकक रुग्णावस्था में हैं या भारी घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इंडियन पल्प एण्ड पेपर टेकनीकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कागज उत्पादक उद्योग के आधुनिक बनाने तथा पुनर्गठित करने की आवश्यकता के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार, कुल 311 एककों में से 77 पेपर एकक उत्पादन संबंधी सूचना नहीं भेज रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) सरकार कागज उद्योग की समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखती है। कागज उद्योग के निरंतर विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए नीतिगत उपाय करना एक अनवरत प्रक्रिया है ।

निगेटिव इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ

1530. श्री बलराम सिंह यादव :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1990 के इंडियन एक्सप्रेस

में "निगेटिव इंडस्ट्रीयल ग्रोथ फियर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के पहले छ: महीनों के दौरान औद्योगिक विकास की अनुमानित दर क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष प्रोत्साहन देकर आगामी महीनों में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) (क) 24 दिसम्बर, 1990) के इंडियन एक्सप्रेस में "नैगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ फीयर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में यह विचार व्यक्त किया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के कारण तीसरी तिमाही (अक्तूबर–दिसम्बर, 1990 में औद्योगिक विकास भी नकारात्मक हो सकता है ।

(ख) सी एस० ओ० द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1990 के दौरान कुल मिलाकर विकास दर 11.7 प्रतिशत थी ।

(ग) और (घ) सरकार अधिक उदार लाइसेंस नीति बनाकर प्रक्रिया संबंधी बाधायें हटाकर तथा राजसहायता व रियायती वित्त उपलब्ध कराके औद्योगिक विकास में और गति लाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। औद्योगिक विकास की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से उद्योग को मूलभूत कच्चे माल की पर्याप्त एवं उचित समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Ayodhya incident

1531. SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there was any understanding between the paramilitary forces/District Magistrate of Faizabad and the IKar-Sswaks that the Kar Sewaks should be allowed to climb the Babri Masjid; &nd

(b) what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) No such report has been received by the Government.

(b) Does not arise.

खादी और ग्राम उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी

1532. श्री राम जेठमलानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 43 लाख कर्मकार खादी और ग्राम-उद्योगों में रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अर्जन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में नियोजित इन कुशल और अकुशल कर्मकारों को सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है ;

(ग) यदि हां, तो सरकारी अनुमान के अनुसार खादी क्षेत्र में नियोजित कर्मकारों की वार्षिक आय क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि खादी क्षेत्र में निर्मित सामान का अन्य-अन्य देशों को निर्यात किया जाता है और गत वर्षों के दौरान निर्यात में भी निरन्तर वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कर्मकारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए सरकार क्या कारगर उपाय करने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) जी, हां।